[श्री मनुभाई कोटाडिया]

गंडक कमांड क्षेत्र में 224 करोड़ रुपये की योजना की मंजूरी दी थी तो उसको भी बिहार सरकार को उपलब्ध कराया जाए ताकि बिहार सरकार अपने काम को आगे बढ़ाये ।

लेकिन एक बात मैं अन्त में कहना चाहूंगी कि जब तक नदियों के सिल्टेशन को हटाने का काम नहीं होगा सारा जो भी काम बाढ़ नियंत्रण की दिशा में किया जायेगा वह कार्यक्रम विफल होगा । इसलिये सिल्टेशन को हटाने का काम अति आवश्यक है । यह भी उसी के साथ-साथ सत्य है कि सिल्ट हमेशा होता ही रहेगा क्योंकि हिमालय की नदियां चूंकि हिमालय सब से कम उम्र की पर्वत श्रृखला है और मिट्टी बहुत नदियां बहा कर लाती हैं और इससे सिल्टेशन होगा ही और सिल्टेशन को हटाना भी पड़ेगा ।

महोदय, ये दोनों ही बातें सत्य हैं तो माननीय मंत्री जी ये दोनों काम करने के लिये अगर आश्वासन देते हों तो मुझे अपना प्रस्ताव इन के अनुरोध पर, उसको वापस लेने में कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन मंत्री जी इसका आश्वासन दे दें ?

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Would you like to react, Mr. Minister?

SHRI MANUBHAI KOTADIA: I do not have to reply to anything. I have already assured that I will do my best.

SHRIMATI KAMLA SINHA: Thank you very much. Sir, in view of what he has said, I will withdraw my Resolution.

The Resolution was, by leave, withdrawn.

RESOLUTION REG. AFGHAN NATIONAL RECONCILIATION PROGRAMME.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mr. Chaturanan Mishra to move his Resolution.

SHRI CHATURANAN MISHRA (Bihar): Sir, I beg to move the following Resolution:

"This House slpports the national reconciliation programme of President Najibullah of Afghanistan, urges upon all parties concerned to take appropriate measures to end blood-shed in Afghanistan, and appeals to the people all over the world to make their contribution for the cause of peace in the region."

उपसभाध्यक्ष महोदय, अफगानिस्तान में पिछले 10–12 साल से जो खून बह रहा है उससे सारा विश्व चिंतित है । सब से बड़ी दिक्कत की बात तो यह है कि जो लोग इस तरह के खून बहाने में अगुवाई कर रहे हैं, उसको एक सुपर राष्ट्र अमरीका की तरफ से पूरी मदद दी जा रही है और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान उसके लिए अपनी भूमि भी दे रहा है और वहां से उन लोगों को हथियारबद करके, ट्रेनिंग दे करके, अफगानिस्तान के अन्दर यह युद्ध चलाया जा रहा है ।

पाकिस्तान की कुछ ऐसी नीति है कि वह अफगानिस्तान में भी ऐसा कर रहा है और वह हमारे देश में भी उसी तरह की खुराफात काश्मीर और दूसरी जगहों में कर रहा है जिससे हम सभी अवगत ही हैं । यही नहीं, अभी कुवायत मसले पर उसने अमेरिका के कहने पर अपनी फौज सऊदी अरब में भी भेज दी है । पाकिस्तान इस तरह अपनी भूमि को बदनामी के काम के लिए इस्तेमाल करने दे रहा है । यह काफी चिंता की बात है । अभी जिस विषय की मैं यहां चर्चा कर रहा हूं, वह अफगानिस्तान के संबंध में है ।

अफगानिस्तान और भारत के बहुत पुराने संबंध हैं और दोस्ताना भी हैं । मैं आज से करीब 15 दिन पहले एक मिशन में काबुल गया था और हमारे

साथ पार्लियामेंट के अन्य सदस्य भी थे। हमने पाया कि वहां लोगों में भारत के प्रति बड़ी श्रद्धा है, न सिर्फ सरकारी स्तर पर बल्कि दूसरे लोगों में भी बड़ी चर्चा है। वहां भारतीय मूल के काफी नागरिक भी हैं--सिख लोग हैं, हिन्दू लोग हैं जो कपड़े का व्यापार करते हैं। मैं वहां उनके गुरुद्वारे में गया और उनसे बातचीत की। वे बड़े ही मेलजोल के साथ अपना जीवन बिता रहे हैं। यह हमारा पड़ोसी देश अफगानिस्तान हमसे बराबर घनिष्ट सम्बंध रखता आ रहा है। सच्चाई तो यह है कि आजादी की लड़ाई जब शुरू हुई, उस वक्त स्वतंत्र भारत की पहली अस्थायी सरकार की स्थापना जो राजा महेन्द्र प्रताप सिंह के सभापतित्व में हुई, उस सरकार की स्थापना भी अफगानिस्तान में ही हुई थी। हमारी आजादी की लड़ाई शुरू करने के बाद तो हमारा उनका मधुर ऐतिहासिक सबंध रहा है। मौजूदा अफगान सरकार से भी हमारी दोस्ती बहुत गहरी रही है। जब दुनिया के लोग कह रहे थे कि प्रेसीडेंट नजीबुल्ला की सरकार सोवियत फौज हटने के बाद एक-दो सप्ताह में खत्म हो जाएगी तब भी हमारी सरकार ने लगातार यही विश्वास व्यक्त किया कि नहीं पर सरकार वहां रहेगी और वही सरकार वहां की जनता की सरकार है। यह हमारी सरकार की धारणा रही है। दोनों देशों के बीच यह जो मित्रता है, इसी कारण जो खैबर घाटी बराबर हमारे आक्रमणकारियों को रास्ता देती थी और हिंदू कुश की पहाड़ी, वह खैबर घाटी मित्रता की घाटी में बदल गयी है। जब तक अफगानिस्तान में हमारी दोस्ती की सरकार है, मित्रता की सरकार है, हम खैबर घाटी से निश्चित रह सकते हैं। अभी अफगान समस्या के निदान के लिए, वहां के राष्ट्रपति नजीबुल्ला साहब ने एक नेशनल रिकंसीलिएशन का प्रोग्राम रखा है। उस प्रोग्राम के तहत उन्होंने यह योजना बनायी है कि अब वहां मल्टी-पार्टी सिस्टम रहेगा। पहले वहां, जैसेकि आप जानते होंगे एक कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार चल रही थी। उन्होंने उसको परिवर्तित कर दिया और मल्टी-पार्टी सिस्टम बना दिया। पहले सरकार के अंदर जो एक ही पार्टी के लोग रहा करते थे, अब उस पार्टी के एक तिहाई के लोग मंत्रीगण हैं और दो-तिहाई दूसरे लोग हैं जिन्हें कि शामिल किया गया है। वहां अब अनेक पार्टीज काम करने लगी हैं और जो लोग बादशाह जहीर के थे, उनकी भी पार्टी और उनके लोग भी काम कर रहे हैं। हम लोग वहां कुछ लोगों से मिले। इस्लामिक पार्टी के लोग, दरकान पार्टी के लोग, सजमने इंकलाबी, सजमने करगना नौजवान, नेशनल सालवेशन पार्टी वगैरह अलग-अलग पार्टियां मैदान में आ गयी हैं और अपना काम करने लगी हैं। वहां की सरकार ने समझौता करने का जो यह प्रयास किया है, उसमें यह जो बगावती मुजाहिदीन लोग थे, उनके जो लोकल कमांडर्स थे, उनसे बड़े पैमाने पर उन्होंने समझौता कार्यक्रम शुरू किया है। हम लोग ऐसे कुछ लोगों से मिले भी। एक आश्चर्यजनक बात है, लेकिन यह सच्ची बात है कि जब सोवियत फौज थी और नजीबुल्ला साहब की सरकार भी थी, दोनों मिलकर जब लड़ रहे थे तब मुजाहिदीनों का सही ढंग से मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। उनको नहीं हरा पा रहे थे। जब सोवियत चले गए और अफगानिस्तान की सरकार ने खुद उनका मुकाबला करना शुरू किया तो वहां के लोगों में देशभक्ति की भावना जागी। आप जानते ही हैं कि अफगान बड़े ही देशभक्त और आजाद मिजाज के लोग हैं। उन्होंने उनको खदेड़ना शुरू किया। अब सिर्फ एक ही प्रांत है, एक ही सूबा है, जहां विद्रोही लोग, सरकार की तरह तो नहीं, लेकिन काम कर रहे हैं, जहां वे मजबूत है। बाकी इलाकों में छुटपुट ही लड़ाई चल रही है, कभी-कभी गुरिल्ला लड़ाई। बाकी जगहों पर सरकार ने अपना कब्जा जमा लिया है। अब तो अमरीका वाले भी मानने लगे हैं कि प्रेसिडेंट नजीब की सरकार टिकी हुई है, जमीन पर है और वह रहेगी। इस तरह से पहला काम तो उन्होंने यह किया कि नेशनल रिक्न्सीलिएशन में, कि सभी पार्टी का मल्टी पार्टी सिस्टम जारी कर दिया है। दूसरा काम यह किया है कि लोकल कमांडरों के साथ समझौता किया है और करीब एक लाख ऐसे

[श्री चतुरानन मिश्र]

सिपाही जो पहले विद्रोही थे, अब अफगान सरकार के मातहत चले गए हैं और उसकी तरफ से अपने-अपने क्षेत्रों में राजकाज चला रहे हैं। तीसरा मुद्दा यह किया है कि जो विद्रोही पाकिस्तान में हैं या ईरान में हैं, उनको भी उन्होंने निमंत्रण दिया है कि आप भी चले आइए और मिल-जुलकर के सर्वदलीय सरकार बनाइए, इस देश को चलाइए, खून-खराबा बंद कीजिए।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, वह चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। यही नहीं, वहां की सरकार निष्पक्ष चुनाव कराएगी। उन्होंने कहा है कि राष्ट्र संघ की देखरेख में यह चुनाव कराए जाए, इस बात को भी उन्होंने स्वीकार किया है। इसके बाद भी अमरीकी सरकार अड़ी हुई थी कि नहीं, प्रेसीडेंट नजीब हट जाए तभी कुछ हो सकता है। आप जानते हैं कि जेनेवा समझौता हुआ था, उसमें पाकिस्तान की सरकार और अमरीका की सरकार ने कुछ वायदे किए थे, लेकिन उनको निभाया नहीं। अभी जब हम लोग वहां गए, तो मालूम हुआ कि प्रेसीडेंट नजीब ने एक नई बात उसमें जोड़ दी है कि चुनाव कराने के लिए एक प्रोवीजनली सरकार, सर्वदलीय सरकार, जो लोग सीज फायर के लिए तैयार हो और मिल-जुलकर के देश का काम, देश का विकास करने के लिए तैयार हों, उनसे मिलकर के बने और उस प्रोवीजनल सरकार के मातहत देश के चुनाव कराए। इसकी अच्छी प्रतिक्रिया दुनियां में बहुत जगह हुई और हम लोगों को यह भी सूचना मिली कि फ्रांस और इटली ने अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन्स फिर से कायम कर लिए हैं और उनके राजदूत वहां आने लगे हैं। सारा काम इस ढंग से चल रहा है। इस स्थिति को देखते हुए हमारा यह कर्त्तव्य होता है और भारत सरकार का भी यह कर्त्तव्य होता है कि हम प्रेसीडेंट नजीब के नेशनल रिकंसीलएशन प्रोग्राम के फेवर में दुनिया में एक वातावरण बनाए, दुनियां के राष्ट्रों से अपील करें, जिससे वहां खून-खराबा बंद हो।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारा ख्याल है कि अब नेशनल रिकंसीलिएशन प्रोग्राम में इन शर्तों को मान लिया है। इसके अलावा एक और काम किया है, जो इन लोगों का कहना था कि यह सरकार, चूंकि कम्युनिस्ट सरकार थी पहले, इस्लाम विरोधी है और इसलिए वे जिहाद किए हुए थे तो वहां की सरकार ने अपने संविधान में इसका प्रावधान कर दिया है—वह इस्लाम के उसूलों के मातहत काम करेंगे और इस्लामिक रिपब्लिक के नाम से काम करेंगे। जब इतनी बात हो गई है, तो मैं अपेक्षा करता हूं कि हमारी सरकार एक नया दृष्टिकोण इन सारी चीजों के बारे में बनाएगी। मैं चाहता हूं कि जैसे सिक्स नेशन्स अपील पहले की जाती थी विश्व की महत्वपूर्ण समस्याओं के बारे में, वैसी हमारी सरकार पेशकदमी ले, इस काम को किया जाए। नॉन-एलाइन मूवमेंट है उसकी तरफ से कोशिश की जाए, यह पेशकदमी भारत को लेनी चाहिए और दुनियां भर में एक वातावरण बनाया जाए, जिससे वहां खून-खराबा बंद हो।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे राष्ट्र-हित में भी यह बात है कि हम इस काम को करें। आप जानते हैं कि इस्लामिक फ़ंडामेंटलिस्ट के नाम से एक जोरदार आंदोलन चला है और वह सऊदी अरब से लेकर पाकिस्तान तक है और कश्मीर में भी ऐसे लोग प्रयास कर रहे हैं इस्लामिक फ़ंडामेंटलिस्ट के नाम पर। यह पूरी चेन जो है सऊदी अरब से लेकर, पाकिस्तान में, और हमारी सीमा में भी प्रवेश कर रही है, इस पूरी चेन में अगर कोई मिसिंग लिंक है, तो वह है अफ़गानिस्तान और अभी हमने आपसे चर्चा की कि अफ़गानिस्तान के अंदर हिंदू हों, या सिख हों या दूसरे मजहब के लोग हों, उनको पूरी आजादी है और वे स्वतंत्रता के साथ अपना काम कर रहे हैं।

इसलिए इस्लामी फ़ंडामेंटलिस्टों की बाढ़ को रोकने के लिये जरूरी है कि

अफ़ग़ानिस्तान सरकार की हम भरपूर मदद करें ।

प्रसन्नता की बात है कि हमारे देश में राष्ट्रपति नजीबुल्लाह आने वाले हैं । मुझे सूचित किया गया है कि 30 अगस्त को वे आने वाले हैं । यह अच्छा होगा कि हमारे सदन की ओर से जो प्रस्ताव मैंने रखा है, इसको एकमत से हम पारित करें और एक तरह से यह उनका स्वागत ही है कि सारे विश्व में इसकी चर्चा चले । फिर भी कुछ बातें हैं जिनकी ओर मैं अपने विदेश मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करूंगा । वहां के लोगों ने कहा कि अफ़ग़ानिस्तान सरकार तो दिल्ली हवाई जहाज भेजती है लेकिन भारत सरकार एयर इंडिया काबुल सर्विस बंद किए हुए है । वे एक तरफ़ा सर्विस चला रहे हैं, भारत सरकार नहीं चला रही है । मैं यह जानना चाहूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है ? अगर आप कहें कि लड़ाई हो रही है तो उनके जहाज तो आ रहे हैं और यहां से लोग जा भी रहे हैं तो फिर आप एयर सर्विस को क्यों नहीं चालू करते ? वहां के शिक्षा मंत्री, कृषि मंत्री या दूसरे मंत्रियों से हमारी बात हुई, उन लोगों ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में, खेती के क्षेत्र में, छोटे उद्योगों के क्षेत्र में और व्यापार में भारत काफ़ी मदद कर सकता है । उन्होंने कहा कि उनकी शिक्षा के लिए, अनुसंधान के लिए, कृषि के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए, रिसर्च इंस्टीटयूट कायम करने के लिए भारत बड़ी मदद कर सकता है । उन्होंने कहा कि अंग्रेजी टीचिंग के लिए, पहले जो भारत में स्कूल चल रहे थे अब बंद कर दिए गए हैं, अगर आपके शिक्षक आएं तो वे हमारे यहां पढ़ा-लिखा सकते हैं और हम उनको काम लगा सकते हैं । उनके शिक्षा मंत्री एक महिला हैं और उन्होंने इस बात की बड़ी इच्छा प्रकट की है कि आपको इस क्षेत्र में हमारी मदद करनी चाहिए । हमारी सरकार ने कुछ दिन पहले घायलों की मदद के लिए दवा भेजी थी, उसमें वे लोग खुश भी थे और वे कह रहे थे कि उनको और भी दवा की जरूरत है ।

मैंने व्यापार के मामले में एक बात देखी और जो वहां के भारतीय मूल के व्यापारी थे उन्होंने भी कहा, इसलिए मैं इसकी चर्चा करना चाहता हूं । भारत के उद्योगपति या व्यापारी वहां नहीं जाना चाहते, जब कि हमारे और उनके राजनैतिक संबंध हैं, डिप्लोमेटिक रिलेशन हैं, लेकिन जापान के साथ उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन भी नहीं हैं परन्तु जापान के व्यापारी वहां जाते हैं और अपना माल बेचते हैं । जब हमने अपने भारतीय मूल के व्यापारियों से पूछा कि आप कपड़ा कहां से मंगाते हैं ? तो उन्होंने कहा कि हम हांगकांग से मंगाते हैं, सिंगापुर से मंगाते हैं, दूसरी जगहों से मंगाते हैं । हमने कहा कि आप भारत से क्यों नहीं मंगाते ? उन्होंने कहा कि एक तो भारत के कपड़े का दाम दूसरी जगह से बहुत ज्यादा है और दूसरा बात यह है कि भारत के व्यापारी और ट्रेड के लोग हमारे साथ पूरा सहयोग नहीं करते हैं । यह शिकायत भारतीय मूल के लोगों की थी कि आपके दाम बहुत ज्यादा हैं और आपके लोग सहयोग भी नहीं करते हैं और आते भी नहीं है । मैं विदेश मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि यह अजीब बात है कि वह देश हमारा सामान चाहता है और हम ही उसके लिए तैयार नहीं हो रहे हैं ! यह कैसी बात है ? इसके बारे में भी विचार होना चाहिए ।

एक और उन लोगों ने शिकायत की कि आपरेशन ब्लू स्टार के बाद वहां के सिख समाज के लोग काफी चिंतित हुए, भारत में भी चिंतित थे और उन लोगों ने प्रदर्शन करना था तो अफगान सरकार ने उनसे बातचीत करके कहा कि भारत हमारा मित्र देश है इसलिए हम चाहेंगे कि आप प्रदर्शन न करें । यह हमारे सिख भाइयों ने भी कहा कि हमारी इच्छा तो थी लेकिन हमने भारत के खिलाफ कोई प्रदर्शन नहीं किया और जो वहां की सरकार का अनुरोध था, उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया । लेकिन हमारे देश को क्या हो गया कि अफगान के जो शरणार्थी हैं, वे हंगामा करते रहते हैं अफगान सरकार

[श्री चतुरानन मिश्र]

के अगर कोई मंत्री आएं या कोई उनके एम्बेसेडर कहीं जायें ? वह तोड़-फोड़ भी कर देते हैं, हंगामा भी कर देते हैं । उन्होंने कहा कि हम तो आपके खिलाफ कुछ नहीं करने देते हैं, लेकिन आपके देश में हमारे खिलाफ होता रहता है। उन्होंने कहा कि अखबारों में अगर कुछ बात छप जाए तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अखबार स्वतंत्र होता है, हमारे दूतावास या मंत्री के खिलाफ आपकी अगर सरकार अनुमति दे दे और ऐसा हो यह उचित नहीं। हम तो आपके साथ मैत्री निभा रहे हैं लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैं सदन से और सरकारी पक्ष से तथा विपक्ष के मित्रों से भी अनुरोध करूंगा कि इस प्रस्ताव को एकमत से हम लोग पारित करें और चूंकि उनके राष्ट्रपति 30 तारीख को यहां आ रहे हैं, यह और भी अच्छा होगा ।

इन शब्दों के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हू इस आशा के साथ कि आज हम सभी मिलकर इसको पारित करेंगे । धन्यवाद ।

The question was proposed.

श्री ईश दत्त यादव (उत्तर प्रदेश) : माननीय उपसभाध्यक्ष जी, श्री चतुरानन मिश्र जी ने इस सदन में जो संकल्प प्रस्तुत किया है वह बहुत महत्वपूर्ण है। दुनियां में शांति रहे, हमारे पड़ौसी देशों में शांति रहे और अफगानिस्तान से भारत के संबंध अच्छे रहें, इन सब के सबध में है। मैं उनके इस संकल्प का स्वागत करता हूं, समर्थन करता हूं । श्री मिश्र जी वहां गये थे, इनकी व्यक्तिगत जानकारी है और जिन बातों को, तथ्यों को उन्होंने प्रस्तुत किया है वह सही हैं। मान्यवर, 20वीं सदी में भी बराबर प्रयास करने के बाद निरस्त्रीकरण प्रस्ताव आने के बाद भी कि दुनियां में शांति रहे अब दुनियां के देश एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं और अगर दुनिया में शांति नहीं रहेगी मान्यवर, किसी तरह से खूनी क्रांति और रिवोल्यूशन होते रहेंगे तो दुनिया का विकास तो रुकेगा ही मानवता का विनाश भी हो जायेगा । मान्यवर, अपने देश में पजाब में, कश्मीर में जो स्थिति है, जिस तरह से हिंसा हो रही है यह बहुत चिंताजनक है। रोज लोग मारे जा रहे हैं, अबोध लोग मारे जा रहे हैं, निर्पराध लोग मारे जा रहे हैं। मान्यवर इस ओर हमारी सरकार प्रयास कर रही है कि अपने देश में भी खून-खराबा रुके और शांति रहे। महोदय, अफगानिस्तान में जो खूनी क्रांति शुरू हुई उसको समाप्त करने के लिए वहां के राष्ट्रपति नजीबुल्लाह साहब ने हर संभव प्रयास किया । उनका प्रयास संराहनीय है लेकिन जो स्थिति भयंकर थी संभवत वह तो अब नहीं रह गयी है । लेकिन फिर भी आज वहां पूर्ण रूप से शांति नहीं हो पायी है । इसलिए यह प्रस्ताव बहुत ही सार्थक है कि अफगानिस्तान हमारा पड़ौसी देश है अतः हमारा कर्तव्य है कि अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए न केवल हम एक प्रस्ताव भेजें, बल्कि दुनिया में भारत इस तरह का वातावरण पैदा करे कि अफगानिस्तान में शांति हो और पूरे विश्व में शांति हो जाये।

हमारे विदेश मंत्री जी अभी कई देशों की यात्रा से लौटे हैं। कल ही माननीय सदन में उनका वक्तव्य हुआ । पूरे सदन में इसका स्वागत किया और न केवल इस सदन ने बल्कि देश के लोगों ने भी इसका स्वागत किया । विदेश मंत्री जी की जो यात्रा रही है वह दुनिया में, देश में शांति स्थापित करने के लिए एक बड़ा क्रांतिकारी कदम रहा है। साथ ही खाड़ी के देशों में हमारे जो भारतीय मूल के लोग फंसे हुए थे उनको वहां से सुरक्षित ले आने के लिये, उनके जानमाल की हिफाजत के लिये विदेश मंत्री जी ने प्रयास किये। नेशनल फ्रंट की सरकार इस तरफ सक्रिय है मान्यवर, अपने देश में शांति स्थापित हो और दुनियां के और देशों में भी शांति स्थापित रहे। महोदय, दुनिया के सभी देश एक दूसरे के साथ भाईचारे का संबंध रखें, व्यापारिक संबंध रखें, राजनयिक संबंध रखें, इसकी ओर सरकार को अग्रसर

होना चाहिए और वह अग्रसर है ताकि विश्व एक शांतिपूर्ण विश्व के रूप में आगे बढ़ सके। मान्यवर, इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय चतुरानन मिश्र जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि भारत की सरकार अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए हर संभव कदम उठाए। महोदय, अफगानिस्तान से हमारे अच्छे संबंध हैं, वह हमारा मित्र देश है, इसलिए वहां जो भी मदद दी जा सके दी जाए—चाहे वह आर्थिक मदद हो या दूसरी मदद हो और अफगानिस्तान में शांति स्थापित करने के लिए भारत सरकार हर तरह की सहायता करे और वहां शांति का वातावरण तैयार करने में मदद दे। धन्यवाद।

डा० अबरार अहमद खान : (राजस्थान) माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं श्री चतुरानन मिश्र के संकल्प का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। महोदय, यह वास्तव में बहुत आवश्यक है कि हमारे पड़ौसी देश अफगानिस्तान में खून-खराबा बंद हो, वहां शांति और स्थिरता रहे। अगर हमारे पड़ौसी देश में स्थिरता रहती है, स्थिर सरकार रहती है, खून-खराबा नहीं होता है तो उसका सीधा प्रभाव हम पर भी पड़ता है और इस सब में यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आज के जो राजनयिक हालात हैं उनमें पाकिस्तान की जो स्थिति है, पाकिस्तान की हमारे प्रति जो भावना या दुर्भावना है वह किसी भी रूप में छिपी हुई नहीं है। जिस प्रकार से वह मुस्लिम देशों में, अरब कंट्रीज में भारत के विरुद्ध लोगों की विचारधारा बनाने या बदलने का प्रयास कर रहा है, जिस प्रकार से वहां की पूर्व प्रधानमंत्री सभी अरब देशों में जाती थीं और भारत के विरुद्ध आलोचना करतीं थीं, वह वास्तव में बहुत चिंता का विषय है।

अफगानिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो वास्तव में हमारा सच्चा साथी रहा है, सच्चा दोस्त रहा है, हर वक्त हमारी मदद के लिए खड़ा रहा है और हमारी सुरक्षा के लिए वह हिमालय की तरह काम में आता है। ऐसी स्थिति में ऐसे मुल्क में स्थिर सरकार रहे, स्थिरता रहे, यह हमारी सुरक्षा के लिये बहुत जरूरी है। तो वहां के लिये एक अच्छी कल्पना करना, एक अच्छा संकल्प लेना, स्थिरता की बात करना, सुरक्षा की बात करना न सिर्फ उनके हित में है बल्कि हमारे भी हित में है। महोदय, यहां मैं अरब देशों के बारे में एक क्लासिफिकेशन करना चाहूंगा कि अरब देश हमारे भी दोस्त रहे हैं, हमारे दुश्मन नहीं रहे हैं लेकिन आज के हालात में अरब देशों के निवासियों और अरब देशों के शासकों में एक बड़ी लाइन खिंच गई है। वर्तमान परिस्थितियों में अरब देशों के शासक पूर्ण रूप से अमरीका की कठपुतली बन गये हैं। अमरीका जो कह रहा है वह उसी की लाइन पर चल रहे हैं लेकिन अरब निवासी उस लाइन पर नहीं चल रहे हैं यह इसी से स्पष्ट हो जाता है कि अरब मुल्कों में वहां की एम्बैसीज को जिस तरह से वहां के निवासियों ने घेरा, यह इस बात का प्रतीक है कि जो कुछ अमरीका कर रहा है वह प्रत्येक अरब निवासी को पसन्द आये, ऐसी बात नहीं है।

तो आज जो हालात बन गये हैं, अमरीका जो चाहता था कि किसी भी तरह से एशिया महाद्वीप के अन्दर वह अपना जमावाड़ा जमाये, इन हालातों में उसको दुर्भाग्य से ऐसा मौका मिल रहा है और अरब देशों में उसने इतनी बड़ी फौजें जमा दी है। मैंने अभी दो रोज पहले भी कहा था कि करीब ढाई लाख सैनिक उसने वहां भेज दिये, 50 जंगी जहाज भेज दिये, 500 लड़ाकू विमान भेज दिये। सैटेलाईट से वह दुनिया के प्रत्येक भाग की तस्वीर ले सकता है और न सिर्फ ईराक बल्कि भारत की तस्वीर भी वह ले सकता है। वह आकाश के अन्दर ही अपने जहाजों में ईंधन भर सकता है। यह सारी व्यवस्था उसने कर रखी है। वह जो वर्षों से चाहते थे उनकी वह आकाक्षायें पूरी हुई हैं, ऐसी स्थिति में जब असुरक्षा के बादल मंडरा रहे हैं, हमारा पड़ोसी देश हमारी

[डा० अबरार अहमद खान]

मदद के लिये हमारा शुभचिंतक रहा हो, उनके लिये हम सोचें और यह संकल्प लें। जो हमारे देश की आंतरिक स्थिति है उन पर भी हम निगाह डालें तो हमारे यहां काश्मीर में जो हालत है उसके बारे में कहने की आवश्यकता नहीं है। बहुत लम्बी बात नहीं है, लेकिन मैं अगस्त 1989 में सपरिवार जम्मू-कश्मीर गया था। उस समय वहां पूरी तरह से शांति थी लेकिन चन्द महीनों के बाद ही वहां के हालात ऐसे बने हैं कि जिस प्रकार से पाकिस्तान ने वहां पर ट्रेन करके मिलिटेंट भेजे हैं उससे दिन ब दिन हालात बिगड़ते गये हैं और बिगड़ते जा रहे हैं और वहां की स्थिति चिंता का विषय है। वह मिलिटेंट अफगानिस्तान से काश्मीर बार्डर के माध्यम से आते हैं। तो हमारा कोई पड़ोसी देश जो हमारे लिये हमेशा शुभ सोचता है, हमारे लिये मददगार रहता है, अगर वहां मजबूती रहती है तो वह हमारे लिये बहुत फायदेमन्द होती है।

महोदय, मैं आपका इशारा समझ रहा हूं। इसलिये अधिक समय न लेकर मैं संकल्प का समर्थन करता हूं और हम अफगानिस्तान के राष्ट्रपति नजीबुल्ला के समन्वय के समर्थन का कार्यक्रम है उसका हमें समर्थन करना चाहिये। धन्यवाद।

श्री शब्बीर अहमद सलारिया (जम्मू और कश्मीर) : जनाब वाइस चेयरमैन साहब, जनाब चतुरानन मिश्र साहब ने इस हाउस में जो रेजलूशन पेश किया है वह अफगानिस्तान के हालात के मुतल्लिक है और इसमें जिस राय का इजहार किया गया है वह यह है कि अफगानिस्तान में जो कोशिशें मिस्टर नजीबुल्ला मुख्तलिफ ग्रुप्स के दरमियान मुफाहमत की कर रहे हैं, वह कामयाब हों उस मुल्क में जो जंगोजदाल जारी है उसका खात्मा हो। उन ख्वाहिशात के साथ किसी को कोई नाराजगी या इख्तिलाफ नहीं हो सकता। नजीबुल्ला साहब का जो काम है वह काफी दुश्वार है क्योंकि अफगानिस्तान में ताहाल रूसी अफवाज की वापसी के बाद कोई इंतखाबात बाकायदा नहीं हुये हैं क्योंकि मुल्क में हालात नासाजगार थे और रूसी अफवाज को मुल्क से बाहर करने के लिये अफगानिस्तान के लोग तगोदोह कर रहे थे। इसलिये वहां पर इंतखाबात का होना बाईद अजइमकान था। अब जबकि अफगानिस्तान के हालात में तबदीलियां पैदा हुई हैं और रूसी अफवाद अफगानिस्तान से चली गई हैं, सवाल यह पैदा होता है कि अफगानिस्तान में जम्हूरी हुकूमत कायम हो, ऐसी हुकूमत कायम हो जिसको तमाम अफगानी भी हिमायत और समर्थन दे। इस मकसद के लिये जो कोशिश मिस्टर नजीबुल्ला कर रहे हैं, उसके लिये हमारे नेक ख्वाहिशात हैं और हम खुदाताला से दुवागो है कि वह इस नेक कदम को पाया तकमील तक पहुंचाने में कामयाब व कामरान हों।

जहां तक भारत देश का ताल्लुक है, हमारे ताल्लुकात प्राचीन जमाने से अफगानिस्तान के साथ चले आये हैं। हमारे मुल्क पर पुराने वक्त में जो चढ़ाईयां हुई और जो कुछ हुआ इसमें अफगानिस्तान के रास्तों को इस्तेमाल किया जाता रहा। तारीख का सबक है कि हमें उस मुल्क के साथ मिलकर ताल्लुकात रखने चाहिए जिस तरह से कि हमारी यह भी ख्वाहिश है कि सारी दुनिया में जो ममालिक है उनके साथ भारत के ताल्लुकात इस्तवार हों और अमन और शांति की फ़िजा कायम हो। लिहाजा चतुरानन मिश्र साहब का यह रेजलेशन काबिले दाद है और इस रेजुलेशन के साथ साथ मैं यह भी कहूंगा कि अफ़गानिस्तान में एक ऐसा सैक्युलर, ऐसी जम्हूरी निजाम कायम हो जिससे कि वहां के लोगों की तरक्की हो। वह बाहमी इंतशार का शिकार न हो जिसके वह शिकार होते चले आये हैं। अफ़गानिस्तान में बेरुनी ताकतों की मुदाखलत और बेरुनी फ़ौजों का सिलसिला खत्म हुआ। मिस्टर नजीबुल्लाह को इस मकसद के हासिल करने के लिए काफ़ी कोशिश करनी पड़ेगी क्योंकि वह गैरमुल्क की फौजों के

वहां आने के साथ तशरीफ़ लाये थे । इसलिए यह और जरूरी हो जाता है कि अफ़गानिस्तान में वह जो कोशिशें कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं ताकि वहां पर मुखालिफ़त ग्रुप के दरमियान, मुखालिफ़त पार्टियों के दरमियान मुफ़ाहमत हो और एक अच्छा निजाम कायम हो । वह कामयाब हों इन अल्फ़ाज के साथ मैं श्री चतुरानन मिश्र की सिफ़ारिश के मुताबिक अपने ख्यालात मुख्तसर करते हुए अपनी तकरीर मुख्तसर करते हुए इसका समर्थन करता हूं । शुक्रिया ।

†[شری شبیر احمد سلاریہ (جموں اور کشمیر) : جناب وائس چیرمین صاحب - جناب چترانن مشرا صاحب نے اس ہاؤس میں جو رزولوشن پیش کیا ہے وہ افغانستان کے حالات کے متعلق ہے اور اسمیں جس رائے کا اظہار کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ افغانستان میں جو کوششیں مسٹر نجیب اللہ مختلف گروپس کے درمیان مفاہمت کی کر رہے ہیں وہ کامیاب ہوں اس ملک میں جو جنگ جدال جاری ہے اسکا خاتمہ ہو - ان خواہشات کے ساتھ کسی کو کوئی ناراضگی یا اختلاف نہیں ہو سکتا - نجیب اللہ صاحب کا جو کام ہے وہ کافی دشوار ہے کیونکہ افغانستان میں تاحال روسی افواج کی واپسی کے بعد کوئی انتخابات باقاعدہ نہیں ہوئے ہیں کیونکہ ملک میں حالات ناسازگار تھے اور روسی افواج کو ملک سے باہر کرنے کیلئے افغانستان کے لوگ تگ و دو کر رہے

†[ ] Transliteration in Arabic script

تھے - اسلئے وہاں پر ا ا ہونا بعید از امکان تھا - اب جب کہ افغانستان کے حالات میں تبدیلیاں پیدا ہوئی ہیں اور روسی افواج افغانستان سے چلی گئی ہیں - سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ افغانستان میں جمہوری حکومت قائم ہو - ایسی حکومت قائم ہو جسکو تمام افغانی بھی حمایت اور سمرتھن دیں- اس مقصد کیلئے جو کوشش مسٹر نجیب اللہ کر رہے ہیں اسکے لئے ہماری نیک خواہشات ہیں اور ہم خدا تعالی سے دعاگو ہیں کہ وہ اس نیک قدم کو پایہ تکمیل تک پہونچانے میں کامیاب و کامران ہوں-

جہاں تک بھارت دیش کا تعلق ہے ہمارے تعلقات پرچین زمانے سے افغانستان کے ساتھ چلے آئے ہیں - ہمارے ملک پر پرانے وقت میں جو چڑھائیاں ہوئی اور جو کچھ ہوا اسمیں افغانستان کے راستوں کو استعمال کیا جاتا رہا - تاریخ کا سبق ہے کہ ہمیں اس ملک کے ساتھ مل کر تعلقات رکھنے چاہئے - جس طرح سے ہماری یہ بھی خواہش ہے کہ سارے دنیا میں جو ممالک ہیں انکے ساتھ بھارت کے تعلقات استوار ہوں اور امن اور آشتی کی فضا قائم ہو - لہذا چترانن مشرا صاحب کا یہ رزولوشن قابل داد ہے اور رزولوشن کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہونگا کہ افغانستان میں ایک

ایسا سیکولر - ایسا جمہوری نظام قائم ہو- جس سے کہ وہاں کے لوگوں کی ترقی ہو - وہ باہمی انتشار کا شکار نہ ہو جس کے وہ شکار ہوتے چلے آئے ہیں - افغانستان میں بیرونی طاقتوں کی مداخلت اور بیرونی فوجوں کا سلسلہ ختم ہوا - مسٹر نجیب اللہ کو اس مقصد کو حاصل کرنے کیلئے کافی کوشش کرنی پڑے گی- کیونکہ وہ غیر ملکی فوجوں کے وہاں آنے کے ساتھ تشریف لائے تھے - اسلئے یہ اور ضروری ہو جاتا ہے کہ افغانستان میں وہ جو کوشش کر رہے ہیں اسلئے کر رہے ہیں تاکہ وہاں پر مختلف گروپس کے درمیان - مختلف پارٹیوں کے درمیان مفاہمت ہو اور ایک اچھا نظام قائم ہو - وہ کامیاب ہوں ان الفاظ کے ساتھ میں شری چترانن مشرا صاحب کی خواہش کے مطابق اپنے خیالات محدود کرتے ہوئے اپنی تقریر مختصر کرتے ہوئے اسکا سمرتھن کرتا ہوں - شکریہ -]

SHRI SUKOMAL SEN (West Bengal): Sir, I rise to support the Resolution moved by my colleague, Mr. Chaturanan Mishra. I feel the Resolution is such that it is befitting that the whole House should support it unanimously.

Sir, I would only say that Afghanistan is our friendly neighbour for a long time, but this neighbouring country has been converted into a hotbed of conspiracy by American imperialism for a long time. Now, as per the Geneva agreement though the Soviet troops have been totally pulled out as per schedule, as per the other stipulation the American Government and the Pakistan Government have not stopped arming the rebels and they are sending them into Afghanistan. That is why the battle is still continuing, although the Afghan Government is in full control of their territory.

Sir, in this situation when the Najibullah Government has appealed for a national reconciliation, it is the duty of our Governmnet to mobilize the support of the entire Non-Aligned Movement, and the Government of India should also support it. render all sorts of economic and material assistance to the Afghan Government so that they can last, so that they can prosper and so that they can improve That is why I support this Resolution and hope the whole House will also support it. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Dr. Reddy, one minute.

DR. G. VIJAYA MOHAN REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I support the Resolution. Sir, India is having the biggest cultural relationship, an age-old cultural relationship, with Afghanistan. Khan Abdul Ghaffar Khan was a revered guest of the Afghan Government. Our relations with Afghanistan are the friendliest and we want resolution of all the problems in Afghanistan. We want President Najibullah's visit to India to become a success and our Foreign Minister to play the due role in solving the problems of Afghanistan in favour of the people of Afghanistan for the independence, suzerainty and non-aligned status of Afghanistan. Thank you.

THE MINISTER EXTERNAL AFFAIRS (SHRI I. K. GUJRAL): Mr. Vice-Chairman, Sir, I am gratified and happy that this Resolution has been supported by all sides. We have a very long tradition of friendship with Afghanistan not only in the mediaeval times but also, most importantly, during our freedom struggle. Khan Abdul Ghaffar Khan is a legend in our country, and I am happy that in this House itself a scion of that great man, Mr. Mohammad Yunus, sits. And when

he sits here I compliment him, particularly because he brings to us memories of those days of freedom struggle which we all shared so well. I am happy that we are in this House not only reviving that memory but also living up to that tradition.

Sir, ever since this problem came in Afghanistan, the Government of India—the various Governments that came—have taken serious note of it. I was Ambassador in Moscow when this trouble began, and that was the time when Mrs. Indira Gandhi was our Prime Minister here. Time and again an effort has been made in some media outside the country to try to confuse the issues by saying that Mrs. Gandhi did not object to the Soviet entry in Afghanistan. Sir. I am a personal witness to the fact that when Mr. Gromyko came here, he had discussions with Mrs. Gandhi, and Mrs. Gandhi most categorically rejected the idea of Soviet entry in Arghanistan. I am conscious of the fact and aware of the fact, and since that was a meeting in which only four persons, Mr. Gromyko the Soviet Ambassador, Mrs. Gandhi and myself, were present, I had kept the detailed notes myself, and now they are on the record of the Ministry. Mrs. Gandhi's vision was very clear about the future of Afghanistan. There were reasons for us not to come out loudly, and the reasons were very obvious because the issues were confused. Rather than our entire region standing together as one to object to foreign intervention, some friends in the West succeeded in dividing the region and they drew a wedge in the region. That is where the arms started coming to Pakistan, and that is where our difficulties began. Therefore, in a way whatever happens to Afghanistan today or happened yesterday or happened the day before yesterday or happened centuries ago has always affected the situation in our country.

Unfortunately, the agony of the Afghan people has continued for much longer than it should have. The Soviet armies have gone home. It is nearly two years now since the withdrawal took place. In these two years also the powers that be and the machinations that go on from the land of Pakistan do not let the Afghan people rest in peace. They do not let them decide their future. They do not let their democratic urges come up.

But, India's foreign policies, again I say, of the Government of last year, of the Government of this year and of the Government before that, have one continuity, and that is that Afghans are our friends, we shall always stand with them, we have always stood with them.

SHRI M. M. JACOB (Kerala): May I ask one question on this? As you have correctly said, we are very much interested to see that there should be normal, peaceful solution of the problems in Afghanistan. What is the initiative taken by India for the normal political settlement in Afghanistan, and how are you trying to prevent Pakistan's interference in the internal affairs of Afghanistan?

SHRI I. K. GUJRAL: Sir, not only this Government but also. the last Congress Government have tried to make efforts in this direction, and we are continuing that. One, of course, is that Mr. Najibullah's Government and his colleagues have our full support. During my tenure in office, the Foreign Minister of Afghanistan has twice visited us, and we found a great deal of similarity in our views about the world situation, about the situation in this rtgion, about the future of Afghanistan. We have both strongly objected to the armed intervention from across the land of Pakistan into Afghanistan.

As a matter of fact, it is a sad chapter for us also because all those arms which were given to Afghanistan for use in Afghanistan, are also being used by terrorists in Kashmir and in Punjab. We also see that those Mujahideens who were trying till yesterday to work for Afghanistan or even today trying to interfere in Afghanistan, are the ones who are training terrorists in POK also. Therefore, there is a great deal of commonality of interest. This is why, when I say that not only in terms of neighbourliness we want the Afghan people to succeed, but we want to have democratic system there. They want to have a non-aligned system there. They want a foreign policy which should be independent. Not only do we support that, but we also see that the end of this era of interventions, of arms inductions, of training of guerillas and also the subversions of the system are something in which we have common interest.

[Shri I. K. Gujral]

It is with this in mind that this Government has invited President Najibullah to come here, and he is coming here on 29th. I am happy that on the eve of his coming here this House, on all sides, is welcoming him. I think this is the nation itself welcoming him because I think on these issues fortunately, on foreign policy issues a sort of bipartisan foreign policy is emerging, and this is what should be because foreign policies ultimately are not party foreign policies, but they are India's foreign policies. Therefore, on all these occasions, I want to repeat again and again that I welcome this type of approach because I don't want to see that on a foreign policy this House should be divided. On foreign policy we should understand each other's point of view and evolve a foreign policy which is consistent with our history, consistent with our tradition and consistent with the ideals that Jawaharlal Nehru spelt out for us. Therefore, I go accordingly there. Therefore, when Mr. Najibullah comes here, I am glad that we always welcome him together.

A few points have been raised by my friends, and I would like to deal with them.

It has been asked why our aeroplanes are not going there.

I am finishing in two minutes.

5.00 P.M.

SHRI CHATURANAN MISHRA: Let him continue for two minutes.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Yes, with the permission of the Prime Minister, he can.

SHRI CHATURANAN MISHRA: This Resolution must be carried.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): The House is with you.

SHRI I. K. GUJRAL: We want to start operating Indian Airlines planes there. That is our objective. But at the moment we have shortage of planes. The moment we have replenished the services definitely it will be our high priority.

Regarding students coming from Afghanistan, they are most welcome her. We have ask d the Afghanistan Government to let us know what type of education they want and to which institutions they want to be sent. I can assure the House that we will do our utmost to accommodate all their needs.

About business, I am glad to say that business there is going on very well between us. There were certain aspects which created difficulties. We are persuaded the businessmen to go there and we find they are ready to go there soon.

I support the spirit of the Resolution. About the wording of it, I have got some difficulty. I will not try to move an amendment, but I would say I welcome the spirit of the Resolution. I am with it. I am glad that this House is unanimously welcoming the visit of the President of Afghanistan.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHASKAR ANNAJI MASODKAR): Mishra Ji, are you withdrawing your Resolution?

SHRI CHATURANAN MISHRA: There is no question of my withdrawing it when all have supported even the spirit of the Resolution.

SOME HON. MEMBERS: We support it, Sir.

(THE DEPUTY CHAIRMAN in the Chair)

SHRI CHATURANAN MISHRA: I thank all the hon. Members for giving support to this Resolution. I request that it should be carried.

THE DEPUTY CHAIRMAN: The question is:

> This House supports the national reconsiliation programme of President Najibullah of Afghanistan, urges upon all parties concerned to take appropriate measures to end blood-shed in Afghanistan, and appeals to the people all over the world to make their contribution for the Cause of peace in the region.

The motion was adopted

THE DEPUTY CHAIRMAN: The motion is adopted unanimously.